Research Chronicler, International Multidisciplinary Refereed Peer Reviewed Indexed Research Journal
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

# भारत के वित्तीय और आर्थिक विकास की यात्रा

**डॉ. रवि प्रकाष पाण्डेय**

*सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शारदा महाविद्यालय, सरलानगर, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)*

**Abstract**

भारत में सर्वप्रथम 1991 में भारत के तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने उदारीकरण निजीकरण विष्वव्यापीकरण की व्यवस्था को अपनाया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मे काफी प्रगति हुई है। 1992 मे विदेषी मुद्रा भंडार जो 1.1 अरब डालर था, तथा भारत को अपना सोना गिरवी रखना पडा था। अब वह बढकर 2017 मे 3 ट्रिलियन डालर हो गया था। भारत में नयी G.S.T. व्यवस्था जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। कर चोरी को रोका गया, F.D.I में 40% की वृद्धि दर्ज की गयी, भारतीय कम्पनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के माध्यम से चीनी कम्पनियों ने 22 विलियन डालर का समझौता किया, इसी प्रकार का समझौता अन्य देषों के साथ भी किया गया, जापान भी 2017 से अगले 5 वर्ष में बुनियादी ढांचें पर और स्मार्ट सिटी के निर्माण पर 35 विलियन डालर के निवेष का वादा किया गया है तथा बुलेट ट्रेन परियोजना में भी जापान का प्रमुख सहयोग रहा है। शरतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों पर आधारित है, कृषि, निर्माण, सेवा इन सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है जो भारत की विषेषता है, डिजिटल इन्डिया को बढावा दिया जा रहा है, व्यवस्था में पारदर्षिता लायी जा रही है, 1.30 लाख करोड अघोषित आय (Black Income) से प्राप्त हुआ जो बडे कारपोरेट डिफाल्टर से प्राप्त हुआ है। कोविड–19 के कारण तथा बार बार के लाकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020–2021 की पहली तिमाही में -21 G.D.P की विकास दर गिर गयी तथा दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिषत का तेज संकुचन देखा गया था लेकिन अब शरतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है तथा आत्मनिर्भर भारत मिषन ने अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित कर दिया , इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि 2025 तक सालाना ग्रोथ रेट कम से कम 9% बनी रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डालर पर पहुच सकती है।

**Key Words:** COVID-19, आर्थिक विकास, कर संग्रहण, उदारीकरण, विष्वव्यापीकरण, निजीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, एफ.डी.आई., विदेषी मुद्रा भंडार, अघोषित आय, ट्रिलियन/विलियन डालर, डिजिटल इण्डिया, डी.बी.टी.।

भारत में सर्वप्रथम 1991 में भारत के तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने उदारीकरण निजीकरण विष्वव्यापीकरण की व्यवस्था को अपनाया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मे काफी प्रगति हुई है। 1992 मे विदेषी मुद्रा भंडार जो 1.1 अरब डालर था, तथा भारत को अपना सोना गिरवी रखना पडा था। अब वह बढकर 2017 मे 3 ट्रिलियन डालर हो गया है तथा भारत में जी यस टी नयी व्यवस्था ने पारदर्षी प्रकिया अपनाकर जो 1 जुलाई 2017

से भारत मे लागू हुई है इस व्यवस्था के माध्यम से कर चोरी को रोका गया है ज्यादा से ज्यादा कर संग्रहण हो रहा है।

भारत का विष्व के षीर्ष एफ डी आई गतंव्य इस प्रकार है

1. भारत $ 63 विलियन डालर
2. चीन $56.6 विलियन डालर
3. इंडोनेषिया $38.5 विलियन डालर
4. मैक्सिको $24.3 विलियन डालर
5. ब्राजील $17.3 विलियन डालर

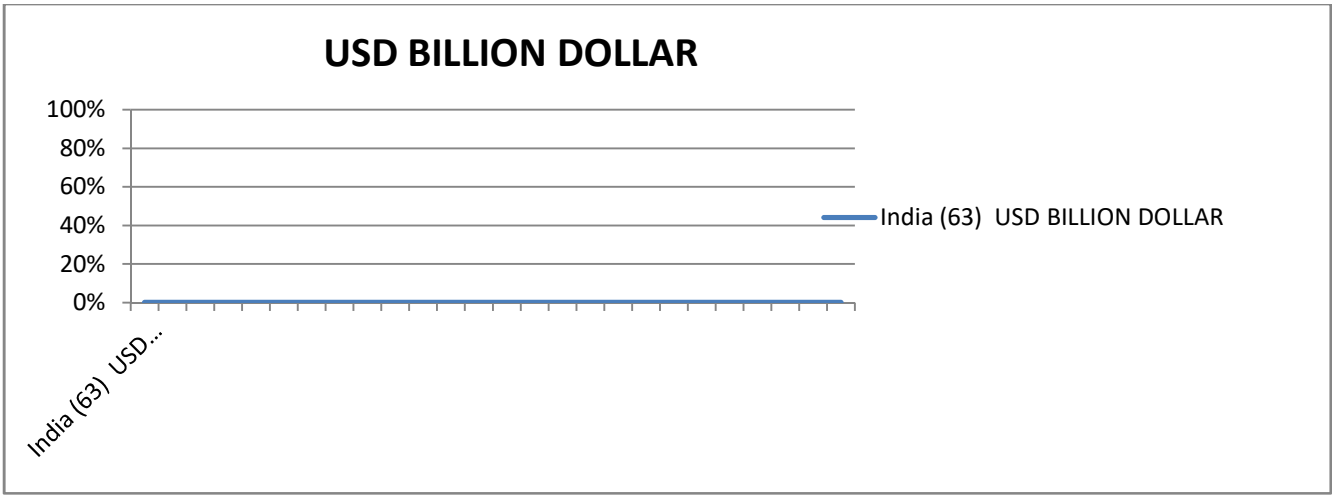


बर्ष 2015 में एफ डी आई में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिषत की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि महत्त्वाकांक्षी योजानाओं को साकार करने के लिए अति आवष्यक है इससे उन कूटनीतिक अभियानों की सफलता प्रदर्षित होती है जिनकी षुरुआत यह सोचकर की गयी थाी कि इनसे विष्व स्तर पर भारत की उभरती हुयी अर्थव्यवस्था के प्रति विष्वास बढेगा भारतीय कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता के माध्यम से चीनी कंपनियो ने 22 विलियन डालर का समझौता किया तथा भारत और ब्रिट्रेन के बीच 9 विलियन डालर का सौदे किए गये जिसमें बोडाफोन का 1.3 विलियन ब्रिट्रिष पांडड का सौदा भी षामिल है जापान ने भी अगले पाँच बर्ष में बुनियादी ढांचे पर और स्मार्ट सिटी के निमार्ण पर 35 विलियन डालर के निवेष का वादा किया गया है

दक्षिण कोरिया ने 10 विलियन डालर का वादा किया गया है 1 विलियन डालर का आर्थिक विकास सहयोग निधी के रूप में और 9 विलियन डॉलर प्राथमिक क्षेत्रों जैसे रेल्वे, विजली, उत्पादन, टांसमिषन इत्यादि।

भारत की अर्थव्यवस्था तीन क्षेत्रों पर आश्रित है कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है । कृषि क्षेत्र में तेजी से तकनीकी का प्रयोग करके कृषि पैदावार को बढावा दिया जा रहा है तथा कृषको की स्थिति को सुधारने के लिए यूरिया की नीम कोटिंग की गई तथा विक्रय फसल की राषि को सीधे ही उनके खातो में सीधे N.E.F.T (नेफ्ट ) या R.T.G.S.(आर . टी. जी.यस) जमा किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री की कृषि सम्मान निधि के माध्यम से छोटे कृषकों की भी स्थिति सुधारी जा रही है।

भारत वर्ष ने (F.D.I) USD-239bn पिछले 5 वर्षों में आकर्षित किया है तथा जिन क्षेंत्रों में अधिकतम F.D.I मिला है जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकम्प्यूनिकषन, व्यापार निर्माण, आटोमोबाइल, विद्युत क्षेत्र तथा आगे सरकार ने वर्ष 2019–2020 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जिसने खुदरा सामान रक्षा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और खाद्यान्न क्षेत्र पर भी छूट देने की घोषणा की।

F.D.I के माध्यम से देष मे विदेषी निवेष आगे आने वाले वर्षा में और भी बढेगा जिससे आधार भूत ढॉचा को बहुत ही बेहतर तरीके से सुधारा जायेगाा

भारत सरकार के सुधारो द्वारा ही 1.30 Laks Crore आधोषित आय कालाधन के माध्यम से प्राप्त हुआ और बजट 2019 में RS. 3 Laks Crore प्राप्त हुआ जो कि बडे कारपोरेट त्रण डिफाल्टर से प्राप्त हुआ है।

डिजिटल इण्डिया 1 जुलाई 2015 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्राी नारेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जिससे डिजिटल इण्डिया व्यापार में 28 दिसंबर 2015 से अप्रैल 2017 में 500 मिलियन की बृद्धि दर्ज की गयी इसीलिए पंचकुला जिला जो हरियाणा राज्य के अंतगर्त आता है। देष में सर्वश्रेष्ट घोषित किया गया है।

विषेषज्ञो का यह मत है कि डिजिटल इण्डिया के कारण सकल घरेलू उत्पाद में 1 ट्रिलियन डालर की वृद्धि दर्ज 2025 तक होगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार में भारी वृद्धि श्रम उत्पादकता के नये नये व्यवसाय को शुरू करना सरकार के आय के स्रोतों में भी डिजिटल इण्डिया के माध्यम से वृद्धि होगी।

भारत सरकार डिजिटल इण्डिया के माध्यम से भारत वर्ष को तकनीक के क्षेत्र में उन्नत बनाना तथा भारत सरकार की सेवाओं को आसनी से आम लोगों तक पहुॅचाना होता है जिससे वह बिना रूकावट के भारत सरकार की सभी सेवोओं की पहुॅच आम जनता तक आसान बनायी जा सकता है

डिजिटल इण्डिया के माध्यम से भारत सरकार ने बैकिंग क्षेत्र में जनधन खातों को खेालकर 1 विलियन भारतीय नागरिको को बैकिंग सेवा से जोडा जा सके इससे यह स्पष्ट हो सके की तकनीक के माघ्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके तथा आधारभूत ढॉचा को भी सुधारा जा रहा है।

डिजिटल इण्डिया के तीन प्रमुख फायदे हैः–

1. तकनीक माध्यम से राष्ट्र का आधारभूत ढॉचे का निमार्ण

2. आम जनता का आर्थिक सषक्तिकरण जैसे सरकार द्वारा पैसा सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में पहुॅचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना कृषक सम्मान निधि सबिसिडी का हस्तांतरण इत्यादि।

3. सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जैसे सरकारी दस्तावेज सीधे प्राप्त करना व्यवस्था में पारदर्षिता आदि।

भारत विष्व में तेजी से डिजिटल होने वाला देष है मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से जुडा है। वर्तमान में 1230 मिलियन भारतीयों ने अपनी डिजिटल पहचान बना ली है तथा भारत में 1210 मिलियन फोन प्रयोग हो रहे है तथा 560 मिलियन इण्टरनेट कनेक्षन भी उपलब्ध है।

सरकार की D.B.T (Direct Benefit Transfer) योजना के माध्यम से 350 मिलियन भारतीय इस व्यवस्था से फायदा ले रहे है तथा नौकरषाही व्यवस्था पर भी काफी अंकुष लग रहा है।

एकीकृत भुगतान पद्धति के माध्यम से पिछले तीन वर्ष 100000 से 800 मिलियन लेनदेन मार्च 2019 तक हुये है जो अर्थव्यवस्था को गति देते है जैसे गूगल प्ले, पे टी एम इत्यादि।

ग्रामीण भारत को भी जोडकर ग्राम पंचायत या गॉव स्तर पर भी डिजिटल इण्डिया के माध्यम से 119000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडा जा चुका है।

भरतीय युवा को भी इसी तकनीक के माध्यम से जोडकर 365000 नागरिक सेवा केन्द्र खोले जा रहे है जो 1 मिलियन से ज्यादा रोजगार 8 प्रतिषत की वृद्धि लागातर 2021–2025 तक प्राप्त करनी होगी तथा 4 प्रतिषत से अधिक कृषि विकास की दर रखनी होगी और सेवा क्षेत्र, को भी अच्छा प्रर्दषन करना होगा और लघु उद्यमियों को भी तैयार किया जायेगा।

इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 2025 तक 5 टिलियन अर्थव्यवस्था बनने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। लेकिन वर्ष 2019 में कोविड–19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पडा है क्योंकि देष में बढ़ते कोविड़–19 के मामले तथा बार बार के लाकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर नकारात्मक में चली गयी तथा कर संग्रहण 20 प्रतिषत तक जी.डी.पी. का भी 20 प्रतिषत कम हो गया तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारी कमी आयी यह अनुमानतः 13. 32 प्रतिषत 2020 में कम हो गया, विष्व पर्यटन संगठन (WTO) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 60 से 80 प्रतिषत तक 2020 में कम हो गया तथा राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 2.7 प्रतिषत से 3.5 प्रतिषत तक G.D.P. का घाटा बढ गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 में मातहत वृद्धि के बाद जनवरी 2020 में फिर से गति प्राप्त करना शुरु कर दिया था, केवल एक वार की सदी के काले हंस कोविड–19 के प्रकोप से रुकी हुई थी, मार्च –अप्रैल 2020 के दौरान लगाये गये कड़े लाकडाउन के कारण अर्थव्यावस्था में वित्त वर्ष 2020–2021 की पहली तिमाही में –21 की गिरावट दर्ज की गई और अगली तिमाही में 7.5 प्रतिषत का तेज संकुचन देखा गया था तब से कई उच्च–आवृत्ति संकेतक ने क्षेत्रों में एक V आकार की वसूली (नीचे से उपर की तरफ आर्थिक वृद्धि) का प्रदर्षन किया क्षेत्रों में एक

असमानता अंतर और प्रेरक शक्ति के साथ अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे लाकडाउन की गति कम होती जा रही है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिषन नें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन के रास्ते पर मजबूती से रखा है इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यदि 2025 तक सालाना ग्रोथ रेट कम से कम 9 प्रतिषत बनी रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डालर पर पहुच सकती है।

**संदर्भः–**

1. Banarjee, A& Dufio(2011)poor Economics, Random House India.
2. Chakraborty, s & Das Gupta, Z (2021, JULY 31) The challenges before NABARD in the midst of RBIS Sterilization Policy. Economic Political Weekly, 45 (31), 71-78.
3. Venkatsubbian, Enterprise and Economic change 50 years of FICCI (New Delhi, Vikas Publishing, House PP-169-172.
4. Vibha Pngla , Rethinking Development State (New Delhi- Oxford University Press, 2000) PP 127-138.
5. Suresh Tendulkar and T-A Bhavani "On Traffic Liberalization understanding reforms" (New Delhi Oxford University Press,2007) P.P.116-125.
6. "राहुल मुखर्जी शरत मे विनियोग" Journal of Development studies vol. 44 no-10 (2008) PP-1425-1445.